

मुख्य समाचार

1. राज्यपाल ने राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी पर जताई चिंता, डीजीपी को पत्र लिखकर जांच में तेजी लाने के लिए निर्देश।
2. जेएसएलपीएस और इंडियन बैंक के बीच करार, क्लस्टर लेवल पर डिजिटल पेमेंट गेटवे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड।
3. राज्य में नीट, जेईई और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए पुलिस मुख्यालय अलर्ट, पुलिस महानिदेशक ने जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाने के लिए निर्देश।
4. राज्य में बदलेगा मौसम का मिजाज, तपती गर्मी से राहत के संकेत, कल से 27 अप्रैल तक राज्यभर में बारिश के आसार।
5. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आज गुड़गांव रवाना होगी झारखंड की पुरुष और महिला खो-खो टीम, खिलाड़ियों में उत्साह।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखकर पुलिस की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। लोकभवन ने सभी जिलों को लंबित मामलों की तुरंत समीक्षा करने और जांच जल्द पूरी करने का आदेश दिया है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जो इस साल एक मई से लागू होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करना और खिलाड़ियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है।

राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रांची में जेएसएलपीएस और इंडियन बैंक के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अब क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाया जाएगा। ऐसी पहल करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

झारखंड के लाखों राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। नामकुम स्थित आरसीएच परिसर में आज स्वास्थ्य विभाग और बीमा कंपनी के बीच ऐतिहासिक एमओयू होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की मौजूदगी में होने वाले इस करार से कर्मचारियों को 5 से 10 लाख रुपये तक के कैंशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

केंद्र सरकार की योजनाओं से कोडरमा जिले की महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है।

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। रांची में डीजीपी तदाशा मिश्र ने समीक्षा बैठक कर 3 मई को होने वाली नीट-2026 सहित जेईई और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने जिला स्तर पर समन्वय समितियों के गठन, प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने को कहा है।

राज्य में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। रांची में डीजीपी तदाशा मिश्र ने समीक्षा बैठक कर प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अफीम की खेती नष्ट करने के निर्देश दिए। अब पुलिस सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए अवैध खेती की पहचान करेगी।

केंद्र सरकार ने देश में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।

कोडरमा स्टेशन की पार्किंग में बीती रात आग लग गयी। लेकिन वार्ड पार्षद मनीष चौधरी और रेलवे कर्मियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन प्रबंधक ने कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई से बड़ी क्षति होने से बच गई।

धनबाद में कुपोषण के खिलाफ जंग तेज हो गई है। जिले में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े के तहत पुराना बाजार के स्लम और टुंडी के सुदूर क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रांची समेत पूरे राज्य में भीषण गर्मी और लू झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, कल से 27 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

राज्य की पुरुष और महिला खो-खो टीमों राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाने के लिए आज गुडगांव रवाना होंगी। 15 दिनों के कड़े प्रशिक्षण शिविर के बाद चुनी गई यह टीम 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित होने वाली नेशनल सुपर स्पीड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।

और अब अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्त नियुक्ति फाइल दोबारा लौटाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।

प्रभात खबर ने लिखा है— सूचना आयुक्तों का मामला लटका, राज्यपाल ने फिर लौटायी फाइल, कहा— जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो, वह कैसे बन सकते हैं सूचना आयुक्त।

दैनिक भास्कर की सुर्खी है— सीएम के आदेश के पांच दिन बाद भी सीआईडी तक नहीं पहुंचा जांच आदेश।

हिन्दुस्तान के शब्द हैं— लांजी में धमाके के लिए एमपी से आया था विस्फोटक।

दैनिक जागरण लिखता है— ऊर्जा निगम के साढ़े छप्पन करोड़ निजी खातों में हुए थे स्थानांतरित।
